> The unit has defaulted in meeting the payment/repayment obligation to the lender and has siphoned of the funds so that the funds have not been utilised for the specific purpose for which finance was availed of nor are the funds available with the unit in the form of other assets."

I recognise that. That is what the Non-Performing Assets mean. This is what has been defined as wilful non-payment. There are circumstances and there do arise occasions on account of fluctuating business situation. For example, steel industry, particularly, goes through a difficult period. The Government cannot work on the basis of wanting to destroy the steel industry. I have to recognise the difficulties and I have to , as best as I can, make a distinction between wilful default and inadvertent default.

SHRI PREM CHAND GUPTA: There are a number of instances. ...(*Interruptions*)... Because of the debate in the House, we should not allow this august House to become a playing field for settling personal scores or corporate wars or media wars.

MR. CHAIRMAN: We have already spent forty-five minutes on this question. ...(*Interruptions*)...We can have a separate discussion on this ...(*Interruptions*)...You give a separate notice for this ...(*Interruptions*)...There are twenty more Members who would like to put supplementaries. Basically, the question has already taken forty-five minutes.

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, एक मिनट।

श्री सभापति: नहीं, एक का होगा तो फिर मुझे सब को अवसर देना होगा।

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, मैंने नाम दिया है।

श्री सभापति : आपका भी है, औरों का भी है। संजय निरुपम का भी है और सब से पहले उसने दिया था। बात यह है कि ...(**व्यवधान**) नहीं।

Promotion of bio-tech industry

*122. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to promote bio-tech industry in the country;

(b) whether Canadian authorities are inclined to promote investment in bio-tach companies in India; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DR. RAMAN SINGH):

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government has taken the following measures to promote bio-tech industry in the country:—

(i) Technology Development Board (TDB) and Pharmaceutical Research and Development Support Fund have been established under Department of Science and Technology for providing soft lans and venture capital funding to the bio-tech industry.

(ii) Special incentives like exemption from Drugs (Price Control) Order 1995, for certain bio-tech products, higher depreciation allowance in respect of R&D expenditure, etc.

(iii) An Expert Group has been constituted in the Department of Bio-technology to identify areas for products and technology oriented research.

(iv) A close interaction has been established between the academia and industry to transfer indigenously developed technologies for commercialization.

(v) FDI up to 100% is permitted on the automatic route for manufacture of drugs and pharmaceuticals, breeding of hybrid sees, bio-fertilizers, bio-tech applications related industries, etc., subject to the condition of prior Government approval wherever it involves use of recombinant DNA technology and specific cell/tissue targeted formulations. Further, Offshore Venture Capital Funds and Foreign Venture Capital companies are allowed to invest in domestic Venture Capital Funds and Venture Capital Undertakings on the automatic route subject to SEBI Regulations and FDI sectoral caps. This is applicable

to both fresh equity investment and acquisition of existing shares. Further, the Venture Capital investors are exempted for SEBI/RBI pricing norms for issue/transfer of shares. These liberal measures have been taken with a view to encouraging FDI in the knowledge industry, including bio-tech industry.

(b) No proposal has so far been received from any Canadian authorities for investment in bio-tech industry.

(c) Does not arise.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Mr. Chairman, Sir, after information techology, major revolutionary changes are taking place in biotechnology. Recently, our Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu, attended a seminar in which a lot of eminent industrialists, bureaucrats, etc. had participated. After seeing the response, our Chief Minister has taken a very good step by providing 350 acres of land for a biotechnology park on the outskirts of Hyderabad. (*Interruptions*) Why are you scared of Chandrababu Naidu? (*Interruptions*) When I take his name, why are you scared? (*Interruptions*) What my State Government is doing, it is my duty to bring to the notice of the Central Government. (*Interruptions*) Sir, You will have to come to my rescue. (*Interruptions*) I have raised this... (*Interruptions*) My State has taken a very good step to promote biotechnology. Two pharmaceutical industries are there. One is Shanta Biotech; and the other is Bharat Biotech. They are producing Hepatitis B virus. So, I would like to know what steps the Government is taking to provide more infrastructures to those States that are taking steps to promote biotechnology. (*Interruptions*)

डॉ॰ रमन सिंह: माननीय सदस्य ने इस क्षेत्र में अपने राज्य में उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि इस सेक्टर में बहुत बड़ी संभावना है। भारत सरकार ने 1982 में बायोटैक्नॉलेजी बोर्ड बनाया था। उसके बाद 1986 से साइंस एंड टैक्नॉलेजी विभाग को अलग विभाग बनाकर सरकार ने इस सेक्टर के महत्व को समझा और सरकार ने इस सारे सेक्टर व इस विभाग को प्रमोट करने के लिए आर॰ एंड डी फेसिलिटी प्रमोट करने के लिए हूमेन रिसोर्स डवलपमेंट के लिए, प्रोसेस एंड डवलपमेंट के लिए सपोर्ट फॉर मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए और सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर के लिए पिछली सातवीं योजना में वर्ष 1985–90 से लेकर 2002–2007 तक इन सालों में 10294 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। दूसरे और सेक्टर्स में भी खर्च हो रहा है और बहुत सारी रिसर्च इंस्टीटयूट्स हैं जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च हैं,

इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है-इन सब पर 260 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गयी है।

सभापति जी, प्राइवेट सेक्टर में भी इस पर काफी लोग रुचि ले रहे हैं और माननीय सदस्य ने खास तौर से जो अपनी स्टेट की बात कही है कि उन के मुख्य मंत्री जी द्वारा इस सेक्टर में विशेष रुचि ली गयी है और इस के लिए लैंड भी दी गयी है। मैं कहना चाहूंगा कि उस का 100 per cent FDI allowed through the automatic route for manufacturing drugs/ pharmaceuticals, breeding of hybrid seeds, biofertilizers, biotech application-related industries. इस सारे सेक्टर में जो भी स्टेट तेजी से काम करने के लिए तैयार हैं, हमने हंड्रेड परसेंट एफ॰डी॰आई॰ को परमिट किया है। साथ-ही-साथ इस सेक्टर में बहुत सारी छूट भी दी गयी है जिस का लाभ राज्य सरकारें उठा सकती हैं। incentives like exemption from Drug Price Control Order, 1995 for certain biotech products. दूसरे खास तौर से अनुसंधान और विकास के कार्य के लिए भी छूट के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया है जिसमें वह ग्रुप उन टैकनॉलोजी ओरिएंटेड रिसर्च के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाएगा।

महोदय, यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हिंदुस्तान में दो सौ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस सेक्टर के अलग-अलग क्षेत्रों में आर॰ एंड डी॰ का काम कर रहे हैं क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जिसका कि दोहन बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में यह एक ऐसा नया सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा खोज चल रही है। इसके जो खास तीन बायो-टेक सैक्टर में एप्लीकेशन हैं, जिसमें काम कर रहे हैं, उनमें एग्रीकल्चर सैक्टर में, जिसके बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की, हाई ब्रिड, फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में डायगनोस्टिक और थैरोपेटिक, फूड प्रोडक्ट के क्षेत्र में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में, इन सब सैक्टर में सरकार रुचि ले रही है और बहुत सारी छूट इसमें हमने दी हुई हैं। आज की तारीख तक एफडीआई का 172 करोड़ का एप्रूवल दिया गया है। माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विषय में सरकार हर तरह से मदद करने को तैयार है और आज भी जो राशि एफडीआई के थ्रू या सीधे ऑटोमैटिक रूप से आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्राइवेट कंपनी प्रमोट करने के लिए जो एक टैक्नोलोजी पार्क की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव भेजा है, वह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। ऐसे ही अन्य प्रदेश सरकारों से 6-7 सरकारों से उस प्रदेश में, उस क्षेत्र में ऐसे पार्क के डवलपमेंट के प्रस्ताव भी आए हैं। निश्चित रूप से इन सारे विषयों पर सरकार ध्यान देगी।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, the second part of my supplementary is this. The hon. Minister has mentioned that hundred per cent FDI is being allowed in this sector. I would like to know whether any

NRI entrepreneur has applied to the Government of India or whether any other country has come forward for setting up these bio-technology parks in India. Can the hon. Minister name them?

डा॰ रमन सिंह: सर, हैदराबाद के उस स्पेफ्कि प्रोजेक्ट की पूरी इन्फोरमेशन लेकर मैं माननीय सदस्य को बताने का प्रयास करूंगा। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा पार्ट है, जिसमें उन्होंने जानना चाहा था कि इंडो-कनेडियन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया की गई है, मैं सम्माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी तक इंडो-कनेडियन प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मगर सीआईए के माध्यम से वर्ष 2002 में एक डेलीगेशन वहां गया था, जिसमें रैनबेक्सी, शांता बाय, जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया, टैंक, थापर ग्रुप और बहुत सारी कंपनियों के डेलीगेट थे। उन्होंने वहां जाकर वहां के उद्योगपतियों से चर्चा की। आने वाले समय में, वर्ष 2003 में कनेडियन डेलीगेशन के यहां आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके पहले माह सितंबर, 2002 में सीआईए का एक डेलीगेशन इंडो-कनेडियन ज्वायंट वेन्चर के लिए क्या संभावना हो सकती हैं, उन सारी संभावनाओं को तलाश करने के लिए वहां जा रहा है। जैसे ही इस प्रकार के प्रस्ताव सरकार के पास आते हैं, सरकार उनके गुण-दोष के आधार पर विवेचना करेगी और निर्णय लेगी।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, bio-technology is one of the most important developing areas of research in technology around the world and it is welcome that the Government is taking some measures to promote research and development. Sir, there are two areas where a break-through in research and development is absolutely essential. The first is the development of an anti-AIDS vaccine and the other is the anti-HIV medication. Recently, a very big international conference was held in South Africa where the question of drugs for AIDS, which has now assumed pandemic proportions and crores of people around the world are suffering, came up. The Western pharmaceutical companies have priced their drugs so high that no developing nation can take advantage of it. India, on the other hand, has got a tremendous potential for developing drugs effectively and at lesser cost. Is special attention being paid to this area?

Sir, the second area is the area of contraception technology. For decades now, we have been working on an anti-pregnancy vaccine and various other types of contraceptive technologies, but the breakthrough is not forthcoming. Would the hon. Minister be good enough to inform the House what specific interest is being taken in these two very vital areas of development of bio-technology, not only for India, but also for the entire developing world?

डा॰ रमन सिंह: सर, सम्माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर विषय की ओर ध्यान दिलाया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंता और चर्चा का विषय है। खासतौर से एड्स के खिलाफ लड़ाई और इस सैक्टर का मैक्सिमम उपयोग इसमें हम कैसे कर सकते हैं, वैक्सीनेशन का कितना उपयोग कर सकते है, वैक्सीनेशन के संबंध में, वह चाहे एड्स के क्षेत्र में हो, इन्फ्ल्युएंजा, मेनेन्जाइटिस के क्षेत्र में हो या/और डायगोनिसिस के क्षेत्र में हो या एचआईवी, एचबीबी, एससीडी, एचईबी, ट्युबरक्लोसिस और टाइफाइड के क्षेत्र में हो, यह सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें गहन अध्ययन की जरूरत है। वैक्सीनेशन के संबंध में जो जानकारी है, उसके अनुसार बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जो एंटी-एचआईवी, एंटी-एड्स के खिलाफवैक्सीनेशन में उस स्टेज में हैं, ... जिसमें बायोटैक के क्षेत्र का उपयोग करके फ्यूचर में हम सस्ते से सस्ता वैक्सीन दे सकेंगे क्योंकि आज जो एड्स के खिलाफ मामले आते हैं, उसके लिए जो दवाइयां और वैक्सीन हैं, वे बहुत कॉस्टली हैं और इसमें रिसर्च और गंभीरता से विचार-विमर्श चल रहा है। मैं सम्माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में प्रयास हो रहे हैं और सरकार भी इस संबंध में चिंतित है कि ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में रिसर्च का काम हो तथा इस क्षेत्र में ज्यादा नए काम करने की आवश्यकता है, जिनको किया जाएगा।

SHRI B.J. PANDA: Mr. Chairman, Sir, while complimenting the hon. Minister for this long list of liberalisation measures and encouragement that have been provided to this industry, I must comment that in the last 55 years, the track record of our country is that in whichever industry the Government gets very actively involved in encouraging, actually runs itself onto the ground. There are examples of steel industry, there are examples of hotel industry. On the other hand, the one industry where India has won laurels, all over the world, in the last 10 years, particularly, is the IT industry, wherein the Government had a very light touch. Its involvement has been as a facilitator, and not as an active participant. I would urge the hon. Minister to keep this thing in mind. My question is this. Again, while complimenting the hon. Minister, I would like to point out that one important area has not been touched upon in his reply, and that is regarding patents and Intellectual Property Rights. In a hi-tech industry like the bio-tech industry, the investors who are going to put FDI into India, which in turn will provide employment opportunities in India, would like to protect whatever is developed by them. I would like the hon. Minister to comment on what the patent regime in India is. Does it act as a facilitator or does it act as a hurdle? Could he tell us what steps he plans to take in this regard to further encourage this industry?

डा॰ रमन सिंह: सभापति महोदय, बायोटैक के क्षेत्र में खास तौर से सम्माननीय सदस्य की चिंता पेटेंट के संबंध में है और अभी राज्य सभा और लोक सभा में मंजूरी के बाद जो एक कानून बन चुका है, उसके तहत आगे खोज और प्रोटेक्शन के संबंध में भी है। मैं सम्माननीय सदस्य को इसका सारा डिटेल में जवाब भिजवाने का प्रयास करूंगा कि क्या-क्या स्टैप्स या कदम सरकार ने इस संबंध में उठाए हैं।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Mr. Chairman, Sir, today, everybody accepts that bio-tech industry has a tremendous potential, but according to the Confederation of Indian Industries, inspite of the measures that have been stated in the reply--you are taking a lot of welcome measures, you are giving a lot of encouragement--still, it is not growing. Though its anticipated growth is about $ 4 billion in the next 6-7 years, given the present rate of growth, we will not be able to achieve even more than 10 per cent of it, annually. I would like to know from the hon. Minister what steps he is going to take in this regard. Then, besides theoretical encouragement measures, venture capital is the most important thing. To build up bio-tech industry, promotion of venture capital is very improtant. What steps are you taking to build up the venture capital which plays a very vital role in promoting the bio-tech industry?

डा॰ रमन सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इस सैक्टर में ज्यादा से ज्यादा फंड की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। मैं सम्माननीय सदस्य की इस चिंता को समझता हूं और 1985 से अब तक इस सारे सैक्टर को यदि मिला दिया जाए तो पांच हजार करोड़ से ऊपर की राशि खर्च हुई है और आने वाले सात-दस साल के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि यह राशि करीब-करीब पांच गुणा बढ़ जाएगी और इसके लिए बहुत सारे स्टैप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं, पॉलिसीज़ में लिब्रलाइजेशन किया है। आपने जो वेंचर केपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बात कही कि यह कैसे हो सकता है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एफ॰ डी॰ आई॰ का जो परमिशन है डोमेस्टिक वेंचर केपिटल फंड और वेंचर केपिटल अंडरटेकिंग में आटोमेटिड रूट में कर सकता है। एफ॰ डी॰ आई॰ का जो हमारा सैक्टोरल केप्स है और सेबी रेगुलेशन का यदि पालन करते हैं तो इस संबंध में कोई चिंता की बात नहीं है, परन्तु इन दो चीजों का पालन करना पड़ेगा-सैक्टोरल केप्स और सेबी रेगुलेशन का और यदि इन दो चीजों का पालन किया जाता है तो निश्चित रूप से इसमें फंड आने में कोई दिक्कत नहीं है।

DR. C. NARAYANA REDDY: Mr. Chairman, Sir, I understand that India has achieved the status of developing and producing high quality

recombinant DNA- based life saving vaccine, Hepatitis B Vaccine. It has already been mentioned by my hon. friend. I would like to know from the hon. Minister why is this vaccine still being imported for immunisation programmes?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Supply of Piped Natural Gas to Delhi

*123. SHRI B.J. PANDA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in 'The Times of India' dated 17th June, 2002, captioned, "Shortage of pipelines robs Delhi of gas"; if so, what action has been taken to speed up supply of Piped Natural Gas (PNG) to the citizens of Delhi;

(b) the names of the areas which have so far been covered for supply of PNG and the other areas which are proposed to be covered in the next phase;

(c) by when it is expected to cover the entire Capital; and

(d) what are the advantages of Liquified Petroleum Gas over the PNG, both from the cost and safety point of view?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) Yes, Sir. Indraprastha Gas Limited (IGL) has developed infrastructure for supply of Piped Natural Gas (PNG) to 16,000 household consumers with a pipeline length of 250 km. The details of areas already covered and proposed to be covered during the current year *i.e.* 2002-03 is given in the statement (*See* below). IGL plans to connect about 22,000 consumers with PNG by the end of March, 2003. IGL has plans to connect 20 lakh consumers by the year 2020 with PNG supply, which would cover major parts of Delhi.